

भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते वैश्विक परिदृश्य में अर्थव्यवस्था के वैश्विक कारकों की दशा एवं दिशा के संदर्भ में अध्ययन



आशा शर्मा

प्राचार्या,
श्रीमती हेलेना कौशिक महिला
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
मलसीसर, झुन्डुनू
राजस्थान, भारत

रतन लाल सुथार

रिसर्च फ़ैलो,
शिक्षा विभाग,
स्टेट जेएनवी युनिवर्सिटी,
राजस्थान, भारत

सारांश

स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई किन्तु इसका सुझाव विभिन्न प्रकार के नियंत्रकों के साथ समाजवाद की ओर रहा। विदेशी निवेश को हतोत्साहित किया गया। विदेश व्यापार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाये गये। विदेशी मुद्रा विनिमय पर भी नियंत्रण रखा गया और इस प्रकार 1991 तक भारत का एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में विकास किया गया। 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई तथा उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इस प्रकार खुली हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास की शुरुआत हुई। वर्तमान में भारत शेष विश्व से जुड़ा हुआ है और पिछला बीता साल (2018) भारत के लिए विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा दिवालिया कानून जैसे आर्थिक सुधारों के असर से उबरने और सामान्य वृद्धि का साल था। अर्थव्यवस्था में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद मंहगाई कम रही। अब 2018-19 में 7.4 की जीडीपी वृद्धि और उपभोक्ता वस्तुओं में 3.7 फीसदी की सामान्य मंहगाई रहने की अपेक्षा है। वैश्विक स्तर पर वृद्धि में गिरावट आई, जबकि व्यापार के मोर्चे पर उथल-पुथल का नजारा दिखा। मोटे तौर पर भारत में घरेलू कारको से चलने वाली अर्थव्यवस्था है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था से हुए एकीकरण के कारण अब वैश्विक कारको का महत्व बढ़ा है। इसलिए भारत की वृद्धि दर बाह्य एवं आंतरिक तत्वों के मिश्रण पर निर्भर रहती, यद्यपि बाह्य वातावरण मूल रूप से अनुकूल नहीं, 2019-20 में और इसके आगे जहाँ तक नजर जाती है, भारत की आर्थिक वृद्धि का ग्राफ घरेलू कारको से तय होता है, लेकिन तीन ऐसे वैश्विक कारक हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जोखिमपूर्ण होते हैं –

1. वैश्विक वृद्धि मंदी, 2. वैश्विक ब्याज दरों का बढ़ता और 3. संरक्षणवाद।

मुख्य शब्द : संरक्षणवाद, व्यापार घाटा, टेरिफ, ट्रेडवार, वैश्विकरण, उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन।

प्रस्तावना

विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बीच अचानक शुरु हुए ट्रेडवार ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। इस वैश्विक तनाव से भारत सहित दुनिया भर के बाजारों में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया। हाल ही में अमेरिका द्वारा चीन से 14 लाख करोड़ के आयात पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके बाद दुनिया भर के शेर बाजारों में तेज गिरावट आ गई। चीन का शंघाई कम्पोजिट इंडेक्स 5.58 प्रतिशत गिर गया। भारत के सेंसेक्स में भी 0.93 प्रतिशत यानि 363 अंकों की गिरावट आई। ये भारत के लिए सकारात्मक अवसर है। जिससे भारतीय निर्यात में 3.5 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका की मौद्रिक नीति कड़ी होने लगी है और यूरोपीय केन्द्रिय बैंक 2019 में क्रमशः कड़ाई के दौर के लिए तैयार होने लगे हैं। अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने का मतलब है, बाजारों के ब्राण्ड मार्केट में बड़े पैमानों पर बिक्री। इससे चालू खाते में घाटे का सामना कर रहे देशों की मुद्रा एकदम से कमजोर हो रही है। भारत पर भी असर पड़ा और डॉलर की तुलना में रुपये का काफी अवमूल्यन हुआ, लेकिन इस परिस्थिति में भारत के लिए नुकसान की गुंजाइश है तो कुछ 'संकट को मौके में बदलने की चुनौति' जैसे चीन सोयाबीन, कपास और चावल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है जबकि भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। चीन का बाजार, भारत के लिए खुला है, निर्यात बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका भी साबित

हो रहा है। अतः चीन में अमेरिकी निर्यात घटा तो इसका फायदा भारत को, अगर भारत अमेरिका के चीनी आयात का 1 प्रतिशत हिस्से को छीन सकता है तो यह चीन में भारत के निर्यात में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यही मौका अमेरिका में भी मिलेगा। इसका ताजा उदाहरण 'बुरहान शिखर सम्मेलन-2018' में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच व्यापार को लेकर अनौपचारिक बातचीत हुई थी इससे व्यापार को लेकर नये सिरे से पहल हुई है।

अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्विक कारक वैश्विक मंदी

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबीक पिछले तीन वर्षों (2016-18) में वैश्विक वृद्धि का औसत 3.5 प्रतिशत रहा। 2019 में वैश्विक वृद्धि का प्रतिशत 3.7 और 2019 से 2024 तक 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर रहने की अपेक्षा है। वैश्विक वित्तीय संकट से पहले की अवधि (2003-07) की विश्व अर्थव्यवस्था के दौरान 5.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। अर्थात् वर्तमान अर्थव्यवस्था एक मंदी की ओर बढ़ रही है।

वैश्विक ब्याज दरों का बढ़ना

अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने 2018 में ब्याज दरें चार गुना बढ़ा दी है। 2019 में यूरोपीय संघ भी मौद्रिक नीति कड़ी करने की योजना बना रहा है इससे विकसित देशों की आर्थिक गति मंद पड़ सकती है। यदि ब्याज दरों में वृद्धि अपेक्षा से तेज हुई तो इससे उभरते बाजारों में बिकनेवाली शुरु और मुद्रायें कमजोर हो जायेगी। भारत को इस वैश्विक आन्दोलन से आने वाले दस गंभीर आर्थिक तुफान के संकेत (खराब बीज जड़, जमा रहे, अमेरिका विरुद्ध चीन, साइबर युद्ध की तैयारी, यूरोप में लोक लुभावन नीतियाँ, अमेरिका का आंतरिक स्थिति, इनोवेशन का मोर्चा, अनिच्छुकों का गठजोड़, मेक्सिको में वामपंथी, यूक्रेन में तनाव एवं नाइजीरिया में संकट) का न सिर्फ सामना करना पड़ेगा बल्कि आर्थिक वृद्धि का ग्राफ भी ऊंचा रखना पड़ेगा।

संरक्षणात्मक आर्थिक पहल

संरक्षणवाद ग्लोबल व्यापार व वृद्धि के लिए खतरा है और इसमें भारत के लिए भी अपने नतीजे दिख रहे हैं। भूतकाल में एशिया के कई देश अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था का इसलिए बढ़ा सके, क्योंकि व्यापार के लिए बढ़ते खुलेपन के साथ उनकी अर्थव्यवस्था को निर्यात की ताकत मिली। अब उसकी जगह संरक्षणात्मक नीतियां ले रही है यानि अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए ग्लोबल वृद्धि एवं व्यापार पर निर्भर रहने के अवसरों की कमी। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन 2018 के लगभग पूरे उत्तरार्द्ध में ट्रेडवार लड़ते रहे और हाल ही में 6 मई 2019 को 'डोनाल्ड ट्रंप' ने अपने ट्वीट में लिखते हुए अमेरिका द्वारा चीन पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क बढ़ाने का एलान किया। ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति ने पिछले साल दिसम्बर 2018 में मुलाकात के बाद 10 दिनों में समझौता करने की घोषणा की थी। यह सीमा मार्च 2019 में समाप्त हो गई। 10 दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। चीन ने इसी वजह से व चीन से आयात पर टेक्स बढ़ा

सकते हैं, हांलाकि इसके बावजूद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा बातचीत के लिए अमेरिका जायेंगे। अमेरिकी वस्तुओं के लिए चीन तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका सबसे ज्यादा वस्तुओं का आयात चीन से करता है। चूंकि इस समझौते से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल तेज हो गई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव दिखा। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह प्रभाव एक सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, इससे भारत के निर्यात में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी, वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ही निर्यात में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था आज छठे पायदान पर है, हांलाकि प्रति व्यक्ति आय में भारत अभी भी 126वें स्थान पर है।

देश से निर्यात को बढ़ाने तथा व्यापारिक संतुलन लाने के लिए मुख्य रूप से किये जा रहे सुधार एवं उपाय निम्न रूप से दर्शाया गया है :-

विदेश व्यापार नीति (2015-20)

इनकी प्रमुख विशेषताओं में भारत से निर्यात को 900 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाना तथा विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी को 3 प्रतिशत करना। इसके लिए वस्तु व्यापार से संबंधित सभी प्रमुख योजनाओं का विलय कर (एमईआईएस) भारत से वस्तु निर्यात योजना लागू करना। इसमें शामिल योजनाओं में 'फोकस मार्केट स्कीम, फोकस प्रोटेक्स स्कीम' इत्यादि शामिल। इस प्रकार योजनाओं के स्थान पर एक योजना और इस प्रकार निर्यातकों के लिए सुविधाएं। ठीक उसी प्रकार भारत से सेवा निर्यात योजना इसके तहत भी सेवा निर्यात से संबंधित योजनाओं का एक योजना में विलय कर दिया गया है। निर्यातकों को विशेष प्रकार का दर्जा एवं सुविधाएं प्रदान करना। जैसे -

श्रेणी	निर्यात/निष्पादन/मिलियन यूएस डॉलर
वन स्टार	3
टू स्टार	25
थ्री स्टार	100
फोर स्टार	500
फाइव स्टार	2000

उपर्युक्त श्रेणी के अनुसार विभिन्न प्रकार की रियायतों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में प्रचलित विभिन्न योजना जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टेण्डअप, स्टार्टअप, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को भी निर्यात से जोड़ा गया है जिससे विनिर्मित उत्पादकों तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

सेज कानून 2005 को फरवरी 2006 से लागू किया गया है। इसके द्वारा पहले से चले आ रहे निर्यात संवर्धन क्षेत्र (इपीजेड) को प्रतिस्थापित किया गया। सेज का मुख्य पक्ष एक पारिभाषिक क्षेत्र में निर्यात से संबंधित विश्वस्तरीय संरचनाओं का विकास कर निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन तथा उनके निर्यात को बढ़ावा देना। सेज आर्थिक मामलों में देश के अन्दर देश होते हैं, इसके

अन्दर सेज कानून के तहत कम्पनियों की स्थापना तथा उनका संचालन किया जाता है। इनको करो से भी छूट दी गई है। 100 प्रतिशत विदेशी एवं निजी निवेश की अनुमति लगभग 17 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। 4 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ तथा 4 लाख 6 हजार 700 करोड़ का निर्यात हुआ है। इस प्रकार सेज अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सक्षम रहा।

बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) विश्व व्यापार को बढ़ावा देने संबंधी सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है। इसके तहत सदस्य देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किये गये हैं। विश्व व्यापार संगठन के शर्तों के अधीन सदस्य देशों द्वारा बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय समझौते किये जा सकते हैं। जैसे—

पीटीए	एफटीए
दो देशों के बीच प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार के समझौते इसके तहत शुल्क कटौती संबंधित वस्तुओं की सकारात्मक सूची छोटी तथा नकारात्मक सूची बड़ी। जैसे—भारत श्रीलंका के बीच पहले पीटीए फिर एफटीए। इसी प्रकार सार्क देशों के बीच पहले पीटीए फिर सापटा (एसएएफटीए)	व्यापार एवं शुल्क कटौती से संबंधित। सकारात्मक सूची बड़ी और नकारात्मक सूची छोटी। दो देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में घनिष्ठता की स्थिति में इस प्रकार का समझौता किया जाता है।

मुख्य वरियता प्राप्त देश (एमएफएम)

इस प्रकार के दर्जे वाले देश से आने वाली वस्तु सेवाओं को अन्य देश से आने वाली वस्तु सेवाओं से प्राथमिकता दी जाती है। विशेष शुल्क कटौती तथा अन्य रियायतें। जैसे भारत द्वारा पाकिस्तान को एमएफएम दर्जा दिया गया है। यद्यपि 'पुलवामा हमला' 14 फरवरी 2019 के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया गया उपरोक्त दर्जा वापिस ले लिया। इसके अलावा दो देशों के बीच आर्थिक समझौतों के अनेक वैश्विक रूप पाये जाते हैं। जैसे—सीमा शुल्क संघ, साझा बजट बाजार एवं आर्थिक संघ।

भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष जैसी संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। विश्व में विभिन्न देशों के साथ भी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते भारत द्वारा किये गये। इस प्रकार वर्तमान में भारत वैश्विक विश्व का भाग है तथा इससे भारत को विदेशी पूंजी आधुनिक तकनीक विकास में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भागीदारी, सुधारों के लिए प्रोत्साहन, वस्तु एवं सेवाओं के स्वतंत्र व्यापार में भागीदारी, आर्थिक विकास में तेजी एवं जीवन स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ चुनौतियाँ जैसे आर्थिक मामलों में अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा आतंकवाद में कुरीतियों का प्रसार। लेकिन कुछ आर्थिक सुधारों एवं राष्ट्रवाद के

ग्लोबल जोखिमों को भी मात्र देख सकेंगे भारत सरकार की सकारात्मक पहल से। अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। एक स्थिर राजनैतिक सत्ता, सामान्य तेल कीमतें व लगभग सामान्य मानसून और मौद्रिक नीति से कुछ सहारा हमारी अर्थव्यवस्था को इस स्तर के ऊपरी भाग में ले जा सकेंगे जिससे अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हो सकेगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 22 दिसम्बर 2018 को हुई जीएसटी परिषद बैठक में जीएसटी की दरे घटाना एवं जीएसटी नियमों को आसान बनाने के लिए स्वीकृति हुई। जिससे भी आर्थिक वृद्धि को सहारा मिलेगा। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कमी की गई यानि वर्तमान (8 मई 2019 तक) रेपो दर 6 प्रतिशत है। जिससे भी आर्थिक वृद्धि दर को सहारा मिलेगा, साथ ही सूचना तकनीक के माध्यम से 2019-20 में 50 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या की इंटरनेट तक पहुंच होगी। यद्यपि 2016 से विकासशील देशों में (भारत) इंटरनेट के लगभग 10 प्रतिशत विस्तारित हो सका जो कि जीडीपी में 1.33 प्रतिशत वृद्धि देखी गई। 'ए फॉर अफोर्डेबल इंटरनेट' समूह इंटरनेट की लागत कम करने की कोशिशों में लगा है। इनका कहना है कि एक गीगा बाइट डेटा की लागत औसत मासिक आय के 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन, इंटरनेट और सोशल मिडिया सिर्फ ग्लोबल आर्थिक वृद्धि और विकास की ही संभावनाएं नहीं है, बल्कि वे गंभीर संकट में भी ग्लोबल मिडिया के साथ खड़ा होकर आर्थिक संतुलन एवं सामाजिक सांस्कृतिक संतुलन को बनाये रखते हैं। यही इंटरनेट का अर्थव्यवस्था में योगदान। हाल ही में सोशल मिडिया द्वारा डॉनाल्ड ट्रंप को चुनने ब्रिटेन, ब्रिक्सिट, म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ाने, फिलिपिन्स में रोड्रिगो दत्तर्ते को सत्ता में आने में मदद, भारत में तो सोशल मिडिया द्वारा वॉट्सअप पर अफवाह की वजह से 2017 में झारखंड में सात लोगों को मार दिया गया, इससे निपटने के लिए मिडिया साक्षरता में सुधार करना, सोशल मिडिया पर टैक्स लगाना (हाल ही में युगाण्डा सरकार ने सोशल मिडिया में टैक्स लगाने हेतु प्रस्ताव पारित किया) व वॉट्सअप पर बड़े ग्रुप तक मैसेज फॉरवर्ड करना सीमित (केवल पांच मैसेज का नियम, 21 अगस्त 2018 से लागू) कर दिया गया। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें भारत के लिए वरदान है, इसका अर्थ यह हुआ कि चालू खाता सुरक्षित जोन में है और रुपये को ताकत मिलती रहेगी। यद्यपि विश्व अर्थव्यवस्था का वैश्विक परिदृश्य में मंदी के दौर में चल रही है, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के भूराजनैतिक कारकों की वजह से अर्थव्यवस्था के उपयोग में सुधार होने की गुंजाइश देखने को मिल रही है। भारतीय राजनीति में अगर स्थिर जनादेश के साथ राजनैतिक सत्ता लोकसभा में आयेगी तो अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता आयेगी।

वर्तमान भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट 2019-20 केन्द्रिय वित्तमंत्री पियूष गोयल ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि "भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विजन

2022, 2030 तक, जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, न्यू इंडिया साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसा भारत जहाँ स्वस्थ एवं स्वच्छ आर्थिक प्रतिस्पर्धा होगी, जहाँ हर भारतीय के पास अपना घर होगा, जिसमें शौचालय, पानी और बिजली उपलब्ध होगी, जहाँ किसानों की आमदनी दुगुनी हो चुकी होगी, युवा वर्ग एवं महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए भरपूर अवसर होंगे तथा वैश्विक गंभीर समस्या जैसे आतंकवाद के खिलाफ भी एक सकारात्मक दूरगामी परिणाम निकलेगा। जैसा कि हाल ही में भारतीय संसद से 'पुलवामा आतंकवादी हमलों' के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'वैश्विक आतंकवादी' घोषित किया गया जो कि भारत के लिए ही नहीं विश्व परिदृश्य पर भी आतंकवाद के खिलाफ एक सकारात्मक पहल शुरू हुई। साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजेवाद से मुक्त होगा।

2030 विज्ञान के अन्तर्गत भारत सरकार ने दूरगामी परिणामों को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को दस ट्रिलियन डॉलर व सहज सुखद जीवन के लिए भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का निर्माण सहित डिजिटल भारत निर्माण, प्रदूषण मुक्त राष्ट्र, ग्रामीण औद्योगीकरण का विस्तार, स्वच्छ नदियाँ का लक्ष्य, ब्ल्यू इकॉनोमी का दोहन करना, अनन्त आकाश मिशन, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना, मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख करना और 'मिनिमम गवर्नमेंट मेक्सिमम गवर्नेंस' वाले देश में रूपान्तरित करना परम ध्येय है जिससे भी आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक टॉप पांच अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकेगा।

अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक स्वच्छ इकॉनोमी के लिए सार्वजनिक बैंकिंग सेक्टर की भी अहम भूमिका होती है। इसके अन्तर्गत बैंकिंग सेक्टर की भी सफाई जारी है और गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों (एनबीएफसी/एस) से कर्ज भी धीमा पड़ा है जिससे भारतीय सार्वजनिक बैंको में 2019-20 से एनपीए घटना शुरू हो रहा है, परन्तु सार्वजनिक बैंको के कर्ज देने में तेज रहने की संभावना नहीं है। मंहगाई के मौजूदा स्तर से अधिक जाने की संभावना है, यद्यपि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बफर जोन में ही रहेगी। अभी हाल ही में 4 अप्रैल 2019 को मौद्रिक नीति समिति द्वारा पहली मौद्रिक नीति समीक्षा जारी की, जिसमें मंहगाई दर कम से कम 6 महीने तक कम रहने की उम्मीद है। आरबीआइ ने आगामी अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 की छः माही के लिए मंहगाई का 2.9 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक रहने का अनुमान किया गया है। खाने-पीने की वस्तुओं एवं इंधन के दाम बढ़ने के आसार हैं। इसी के संदर्भ में सरकार ने 1 मई 2019 को घरेलू एवं कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर में 6 रुपये की बढ़ौतरी की गई। यह बढ़ौतरी कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण की जा रही है। इसके अलावा आरबीआइ ने कहा की ग्लोबल वित्तीय बाजार में अस्थिरता रहेगी और सरकार का घाटा भी बढ़ेगा। इससे मंहगाई दर में बढ़ौतरी होगी, लेकिन ये भारत सरकार के 4 प्रतिशत के ± 2 के स्तर पर ही रहेगी। हालांकि

आरबीआइ ने जीडीपी विकास का अनुमान 2019-20 में 7.2 प्रतिशत व 3 अप्रैल 2019 को 'एशियन विकास बैंक' ने जीडीपी की विकास दर 7.2 प्रतिशत का अनुमान लगाया था। आरबीआइ द्वारा रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की थी। उम्मीद है कि सार्वजनिक बैंक भी इस वृद्धि को लागू करेंगे तो आम नागरिकों का इसका फायदा मिलने लगेगा। ये इसलिए भी जरूरी है कि ग्लोबल इकॉनोमी की ग्रोथ घट रही है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि 'ये रेपो दर बढ़ना इंडियन इकॉनोमी का ग्लोबल इकॉनोमी के साथ दशा एवं दिशा के लिए सही समय पर लिया गया सही फैसला है क्योंकि व्यापार को लेकर चीन पर इस समय पश्चिमी देशों खासतौर पर अमेरिका का जबरदस्त दबाव है। चीन के साथ अमेरिका का 29 लाख करोड़ रुपये का व्यापार घाटा है। अमेरिका चीन ट्रेडवार से भारत के निर्यात 3.5 प्रतिशत बढ़ने के साथ ही अन्य देशों जैसे वियतनाम, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, फिलिपिंस क्रमशः निर्यात में बढ़ौतरी 5 प्रतिशत, 4.6 प्रतिशत, 3.8 प्रतिशत व 3.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। (यूएनओ का आंकलन) इस मामले में चीन भारत से समर्थन व सहयोग चाहता है। फिर वह 'बेल्ट एण्ड रोड योजना' की बैठकों में भारत की सांकेतिक ही क्यों न हो, मौजूदगी चाहता है, जिससे ग्लोबल स्तर पर योजना को लेकर घटते हुए उत्साह को थामा जा सके। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में चल रहे व्यापार युद्ध से ग्लोबल व्यापार में भारी कमी आयेगी, यद्यपि भारत का निर्यात 3.5 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। व्यापारिक इतिहास के प्रारम्भिक दौर में विदेशी व्यापार लगभग मुक्त ही रहा, बाद के दौर में भारी आयात शुल्क लगने लगे। इस बीच अर्थशास्त्रियों के माध्यम से दुनिया के सभी देश मुक्त व्यापार के रास्ते पर चले, तो सभी देशों को लाभ होगा। ब्रिटिश शासन में वहाँ से आने वाले कपड़े बिना आयाता शुल्क के भारत आने लगे परिणामस्वरूप भारत के उद्योग 'डी-इंडस्ट्रियाइजेशन' हो गये। यद्यपि स्वतंत्रता आन्दोलन के दौर में राजनैतिक दबाव में विदेशी सरकार को भी आयात शुल्क लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। पिछले 28 वर्षों में वैश्वकरण के चलते विभिन्न देशों के बीच में टेरिफ व गैर टेरिफ, सभी प्रकार की बाधाओं को दूर किया गया। मुक्त व्यापार के इस दौर में संरक्षणवाद आर्थिक जगत में एक अभिशाप माना जाने लगा है। इस बीच विश्व व्यापार संगठन (1995) का जन्म हुआ और इसके समझौतों के मद्देनजर ग्लोब में नियम आधारित व्यापार का दूसरा नाम मुफ्त व्यापार हो गया। शुरू में आयात शुल्क घटने व नियम से ग्लोबल बाजार का विस्तार हुआ, फिर डब्ल्यू टी ओ में चीन के आने के बाद स्थितियाँ बदलने लगी और आज विश्व के 130 देशों को चीन के साथ व्यापार घाटा हो रहा है, ऐसे में इन देशों के उद्योग नष्ट हो गये और बेरोजगारी बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बेरोजगारी की दर पिछले पांच सालों में 3 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गई।

अमेरिका ने चीन सहित अन्य देशों से आने वाले सामान पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था अस्वस्थ और अस्वच्छ होती जा रही है। इससे भारत सहित अन्य विकासशील देशों को भी अपने विदेशी

व्यापार नीति बदलने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ऐसे में भारत को इस परिस्थिति में एक सुनहरा अवसर है कि वह अपने उन उद्योगों को पुनर्जीवित कर सके जो सस्ते आयात के कारण बंद हो गये हैं। चीन के माल पर अमेरिका द्वारा रोक लगाने से जिन ग्लोबल सप्लाय चैन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। भारत में ऑटोमोबाईल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता वस्तुओं आदि के निर्माण में लगी विदेशी कम्पनियों अधिकांशतः कलपुर्ज विदेशों से मंगवाती है, इस व्यापार युद्ध में भारत के लिए निष्कर्ष के रूप में एक संभावना है कि नई परिस्थितियों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा मिलना तय है। आयात शुल्क लगने से मध्यम वर्ग के लिए कई साजो सामान अब मंहगा हो गया किन्तु इससे देश में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा व 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलना एक अच्छी अर्थव्यवस्था का द्योतक है। मध्यम वर्ग को होने वाले इस नुकसान की भरपाई देश में उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने से हो रही है।

भारत के लिए 'लंदन कंसल्टेंसी सेन्टर फॉर इकॉनोमिक्स एण्ड बिजनेस रिसर्च' का अनुमान है कि भारत 2019 में ही ब्रिटेन को भी पछाड़ सकता है, वहीं 'वर्ल्ड बैंक' के मुताबिक 15 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, इसके प्रमुख कारण भारत में किये गये आर्थिक सुधारों से ही संभव हुआ। इसी का परिणाम है कि भारत में अब कारोबार करना आसान हुआ है। इसके संदर्भ में हाल ही में 'ईज ऑफ ड्यूंग बिजनेस' में भारत ने 2019 में 190 देशों में 77वीं रैंक प्राप्त की जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुनहरा अवसर है।

निष्कर्ष

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू कारको के साथ कुछ जोखिम पूर्ण वैश्विक कारको संरक्षणवाद, आर्थिक मंदी एवं ब्याज दरों में बढ़ौतरी इत्यादि का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। पिछले वर्षों विशेषकर 2017-18, 2018-19 एवं अब 2019-20 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए एकीकरण के कारण और ज्यादा वैश्विक कारको का महत्व बढ़ गया है जिससे विकासशील देशों (भारत) में आर्थिक मंदी, व्यापार युद्ध विशेष रूप से अमेरिका व चीन के मध्य होने से इन देशों में मौजूदा विश्वस्तरीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इन देशों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ-साथ इन देशों द्वारा निर्यातों में बढ़ौतरी हो सकेगी जिससे इन देशों की स्वच्छ और स्वस्थ अर्थव्यवस्था, मंहगाई एवं बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों का सकारात्मक दृष्टिकोण से संजीवनी मिलेगी और हतोत्साहित उद्योग पुनर्जीवित होंगे। रोजगार में वृद्धि होगी जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का विकास होगा। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इन देशों के लिए मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट की इन परिस्थितियों में भी अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

पत्र-पत्रिकाओं के विशेष इनपुट
द वाशिंगटन पोस्ट
ब्लूमबर्ग न्यूज
द जापान न्यूज
इंडिया टूडे
कॉस्मोपोलियन इंडिया
रीडर्स डाइजेस्ट इंडिया
स्पेन
हार्मनी सेलिब्रेट एज
राजस्थान पत्रिका न्यूज पत्रिका
दैनिक भास्कर न्यूज-अभिव्यक्ति, संपादकीय, रसरंग
संयुक्त राष्ट्र का आंकलन